EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

19 - 25 APRIL 2026

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

EXAM Genius

UPSC SSC BANK RAILWAY STATE EXAMS

Ques: What was the year-on-year growth rate of bank credit in India as of March 31, 2026?

प्रश्न: 31 मार्च 2026 तक भारत में बैंक क्रेडिट की वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि दर क्या थी?

A) 10%
B) 12%
C) 13.4%
D) 15%
E) 16%

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Bank credit in India grew by 16% year-on-year as of March 31, 2026.
- 31 मार्च 2026 तक भारत में बैंक क्रेडिट 16% की दर से बढ़ा।
- Deposits increased by 13.4% during the same period.
- इसी अवधि में जमा (डिपॉजिट) 13.4% बढ़े।
- The data was released by the Reserve Bank of India.
- यह डेटा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया।
- Total deposits stood at ₹267.8 lakh crore, while bank credit reached ₹219 lakh crore.
- कुल जमा ₹267.8 लाख करोड़ रहे, जबकि बैंक क्रेडिट ₹219 लाख करोड़ रहा।
- Investments grew by 4.7% to ₹71.4 lakh crore.
- निवेश 4.7% बढ़कर ₹71.4 लाख करोड़ हो गया।
- In absolute terms, deposits increased by ₹31.7 lakh crore and credit by ₹30.1 lakh crore.
- वास्तविक रूप में, जमा ₹31.7 लाख करोड़ और क्रेडिट ₹30.1 लाख करोड़ बढ़ा।

Ques: What was India's unemployment rate (UR) in March 2026 as per PLFS data?

प्रश्न: PLFS के अनुसार मार्च 2026 में भारत की बेरोजगारी दर (UR) क्या थी?

A) 4.5%

B) 4.9%
C) 5.0%
D) 5.1%
E) 5.5%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• India's unemployment rate rose to 5.1% in March 2026.
• मार्च 2026 में भारत की बेरोजगारी दर 5.1% हो गई।
• It increased from 4.9% in February 2026, marking a five-month high.
• यह फरवरी 2026 के 4.9% से बढ़कर पांच महीने का उच्चतम स्तर है।
• The data is based on the Periodic Labour Force Survey (PLFS) released by the National Statistics Office.
• यह डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी PLFS पर आधारित है।
• Labour Force Participation Rate (LFPR) stood at 55.4% in March.
• मार्च में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 55.4% रही।
• Worker Population Ratio (WPR) declined to 52.6%.
• वर्कर पॉपुलेशन रेशियो (WPR) घटकर 52.6% हो गया।
• LFPR represents the percentage of people working or seeking work.
• LFPR उन लोगों का प्रतिशत दर्शाता है जो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं।
• WPR indicates the proportion of employed persons in the population.
• WPR जनसंख्या में कार्यरत लोगों का अनुपात दर्शाता है।

Ques: As per IMF projections, India is expected to become the world's third-largest economy by which year?
प्रश्न: IMF के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है?

A) 2027
B) 2028
C) 2030

D) 2031
E) 2035

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• According to International Monetary Fund (IMF) April 2026 data, India slipped to the 6th largest economy in 2025 with GDP around $3.92 trillion.

• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अप्रैल 2026 के अनुसार, भारत 2025 में लगभग $3.92 ट्रिलियन GDP के साथ 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा।

• This decline is temporary due to rupee depreciation and GDP base year revision, not due to slowdown in growth.

• यह गिरावट अस्थायी है और रुपये की कमजोरी तथा GDP बेस ईयर संशोधन के कारण है, न कि विकास में कमी के कारण।

• India is projected to become the 4th largest economy by 2027, overtaking Japan.

• भारत 2027 तक जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।

• By 2031, India is expected to become the 3rd largest economy, surpassing Germany.

• 2031 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।

• Despite temporary ranking changes, India remains one of the fastest-growing major economies globally.

• अस्थायी रैंकिंग बदलाव के बावजूद, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

Ques: The 'Super Sales Saathi' mobile app launched by LIC is primarily designed for whom?

प्रश्न: LIC द्वारा लॉन्च किया गया 'Super Sales Saathi' मोबाइल ऐप मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है?

A) Policyholders / पॉलिसीधारक

B) Bank officials / बैंक अधिकारी

C) LIC agents / LIC एजेंट

D) Government employees / सरकारी कर्मचारी

E) Investors / निवेशक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Life Insurance Corporation of India launched two mobile apps — MyLIC and Super Sales Saathi.

• भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने दो मोबाइल ऐप — MyLIC और Super Sales Saathi लॉन्च किए।

• The apps were launched by M. Nagaraju in Mumbai.

• इन ऐप्स को मुंबई में एम. नागराजू द्वारा लॉन्च किया गया।

• Both apps are powered by LIC's DIVE platform (Digital Innovation & Value Enhancement).

• दोनों ऐप LIC के DIVE प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित हैं।

• The MyLIC app is a one-stop platform for policyholders to manage policies, pay premiums, and access benefits.

• MyLIC ऐप पॉलिसीधारकों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जहां वे पॉलिसी प्रबंधन, प्रीमियम भुगतान और लाभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

• Super Sales Saathi is specifically designed for LIC agents with features like customer management and real-time updates.

• Super Sales Saathi विशेष रूप से LIC एजेंटों के लिए बनाया गया है, जिसमें ग्राहक प्रबंधन और रियल-टाइम अपडेट जैसी सुविधाएं हैं।

• The initiative aims to enhance digital services, improve security, and provide a user-friendly experience.

• इस पहल का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाना, सुरक्षा बढ़ाना और उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- LIC – Largest life insurance company in India
- LIC – भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी
- Established – 1956
- स्थापना – 1956
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- DIVE Platform – Focuses on digital innovation and faster services
- DIVE प्लेटफॉर्म – डिजिटल नवाचार और तेज सेवाओं पर केंद्रित

Ques: How many banks have been authorised by the Indian government to import bullion for 3 years starting April 1, 2026, and which two banks are authorised to import only gold?

प्रश्न: भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 3 वर्षों के लिए कितने बैंकों को बुलियन आयात की अनुमति दी है और कौन से दो बैंक केवल सोना आयात करने के लिए अधिकृत हैं?

A) 15 Banks — SBI and HDFC / 15 बैंक — SBI और HDFC

B) 17 Banks — PNB and Bank of India / 17 बैंक — PNB और बैंक ऑफ इंडिया

C) 17 Banks — Union Bank of India and Sberbank / 17 बैंक — यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्बेरबैंक

D) 15 Banks — Union Bank of India and Sberbank / 15 बैंक — यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्बेरबैंक

E) 20 Banks — Deutsche Bank and ICBC / 20 बैंक — ड्यूश बैंक और ICBC

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India, through Directorate General of Foreign Trade

(DGFT), has authorised 17 banks to import bullion for three years (April 1, 2026 to March 31, 2029).

• भारत सरकार ने DGFT के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2029 तक 17 बैंकों को बुलियन आयात की अनुमति दी है।

• Out of these, 15 banks — including State Bank of India, HDFC Bank, Deutsche Bank and Industrial and Commercial Bank of China — can import both gold and silver.

• इनमें से 15 बैंक — जैसे SBI, HDFC बैंक, ड्यूश बैंक और ICBC — सोना और चांदी दोनों आयात कर सकते हैं।

• Only Union Bank of India and Sberbank are authorised to import only gold.

• केवल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्बेरबैंक को सिर्फ सोना आयात करने की अनुमति है।

• Delay in issuing the authorisation list had halted imports, leaving over 5 tonnes of gold and around 8 tonnes of silver stuck without customs clearance.

• अनुमति सूची में देरी के कारण 5 टन से अधिक सोना और लगभग 8 टन चांदी सीमा शुल्क निकासी के बिना अटकी रही।

• India is the second-largest gold importer globally, importing $72 billion worth of gold in 2025–26 (24% increase), while silver imports rose to $12 billion.

• भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोना आयातक है, जिसने 2025–26 में $72 बिलियन का सोना आयात किया (24% वृद्धि), जबकि चांदी का आयात $12 बिलियन तक पहुंच गया।

• DGFT also changed the classification of gold, silver and platinum from 'free' to 'restricted', making licences mandatory for certain importers.

• DGFT ने सोना, चांदी और प्लेटिनम को 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' श्रेणी में डाल दिया, जिससे लाइसेंस अनिवार्य हो गया।

Ques: The 'Water Forward' initiative launched by the World Bank Group aims to ensure water security for how many people globally by 2030?

प्रश्न: विश्व बैंक समूह द्वारा शुरू की गई 'Water Forward' पहल का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर कितने लोगों को जल सुरक्षा प्रदान करना है?

A) 200 million / 20 करोड़

B) 400 million / 40 करोड़

C) 600 million / 60 करोड़

D) 800 million / 80 करोड़

E) 1 billion / 100 करोड़

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• World Bank Group launched the global initiative 'Water Forward'.

• विश्व बैंक समूह ने 'Water Forward' नामक वैश्विक पहल शुरू की।

• The initiative aims to ensure water security for over 1 billion people by 2030.

• इस पहल का लक्ष्य 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों को जल सुरक्षा प्रदान करना है।

• A key feature is the introduction of country-led "Water Compacts".

• इसकी प्रमुख विशेषता देश-नेतृत्व वाले "Water Compacts" का परिचय है।

• Under these compacts, governments will define reforms, strengthen institutions, and create investment pathways.

• इन कॉम्पैक्ट्स के तहत सरकारें सुधारों को परिभाषित करेंगी, संस्थाओं को मजबूत करेंगी और निवेश के रास्ते बनाएंगी।

• The World Bank Group itself targets to provide water security to 400 million people.

• विश्व बैंक समूह स्वयं 400 मिलियन लोगों को जल सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

• The initiative is supported by institutions like Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, European Investment Bank, and New Development Bank.

• इस पहल को एशियाई विकास बैंक, एआईआईबी, यूरोपीय निवेश बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक का सहयोग प्राप्त है।

• The initiative focuses on improving financing and accelerating water-related projects globally.

• यह पहल वित्त पोषण बढ़ाने और जल परियोजनाओं को तेज करने पर केंद्रित है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• World Bank Group – Provides financial and technical assistance to developing countries
• विश्व बैंक समूह – विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है
• Headquarters – Washington, D.C., USA
• मुख्यालय – वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका
• SDG 6 – Clean Water and Sanitation
• SDG 6 – स्वच्छ जल और स्वच्छता

Ques: What was India's trade deficit in FY 2025–26 as per official data?
प्रश्न: आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार FY 2025–26 में भारत का व्यापार घाटा कितना था?

A) $94.6 billion
B) $100.5 billion
C) $110.2 billion
D) $119.3 billion
E) $125.0 billion

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• India's trade deficit widened to $119.3 billion in FY 2025–26.
• FY 2025–26 में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $119.3 बिलियन हो गया।
• It increased from $94.6 billion in the previous financial year.
• यह पिछले वर्ष के $94.6 बिलियन से बढ़ा है।
• The rise was mainly due to higher imports, which grew by 6.4% to $979.4 billion.
• यह वृद्धि मुख्यतः आयात बढ़ने के कारण हुई, जो 6.4% बढ़कर $979.4 बिलियन हो गया।
• Exports also grew by 4.22% to $860 billion.

• निर्यात 4.22% बढ़कर $860 बिलियन हो गया।
• Merchandise exports increased by 1% to $441.78 billion.
• वस्तु निर्यात 1% बढ़कर $441.78 बिलियन हो गया।
• Services exports rose by nearly 8% to $418.31 billion.
• सेवा निर्यात लगभग 8% बढ़कर $418.31 बिलियन हो गया।
• Exports to China increased by $5 billion.
• चीन को निर्यात $5 बिलियन बढ़ा।
• Trade surplus with the United States narrowed to $34.4 billion from $43 billion.
• अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष $43 बिलियन से घटकर $34.4 बिलियन रह गया।

Ques: What is the proposed FDI limit in India's pension sector as per recent news?

प्रश्न: हालिया खबरों के अनुसार भारत के पेंशन सेक्टर में प्रस्तावित FDI सीमा क्या है?

A) 49%
B) 74%
C) 80%
D) 100%
E) 26%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India is considering increasing the FDI limit in the pension sector from 49% to 100%.
• Government of India पेंशन सेक्टर में FDI सीमा 49% से बढ़ाकर 100% करने पर विचार कर रही है।
• The move aims to align the pension sector with the insurance sector, where 100% FDI is already allowed.
• यह कदम पेंशन सेक्टर को बीमा क्षेत्र के अनुरूप लाने के लिए है, जहां 100% FDI की अनुमति है।

• A Bill to amend the PFRDA Act, 2013 is expected in the upcoming Parliament session.

• PFRDA Act, 2013 में संशोधन के लिए एक विधेयक आगामी संसद सत्र में लाया जा सकता है।

• The amendment may be introduced in the Monsoon or Winter Session 2026.

• यह संशोधन 2026 के मानसून या शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।

• Currently, the FDI limit in the pension sector is capped at 49%.

• वर्तमान में पेंशन सेक्टर में FDI सीमा 49% है।

• Earlier, Parliament increased the FDI limit in the insurance sector from 74% to 100%.

• इससे पहले संसद ने बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी थी।

• The amendment may also include separation of NPS Trust from PFRDA.

• संशोधन में NPS Trust को PFRDA से अलग करने का प्रावधान भी शामिल हो सकता है।

• NPS Trust functions may be brought under charitable trust or Companies Act framework.

• NPS ट्रस्ट के कार्यों को चैरिटेबल ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम के तहत लाया जा सकता है।

Ques: As per the RBI's new NBFC Branch Authorisation Directions, 2025, which NBFCs are allowed to expand their branches across India?

प्रश्न: RBI के नए NBFC ब्रांच ऑथराइजेशन दिशानिर्देश 2025 के अनुसार किन NBFCs को पूरे भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति है?

A) NBFCs with NOF up to ₹50 crore / ₹50 करोड़ तक के NOF वाले NBFCs

B) NBFCs with low credit rating / कम क्रेडिट रेटिंग वाले NBFCs

C) NBFCs with NOF above ₹50 crore and AA or above rating / ₹50 करोड़ से अधिक NOF और AA या उससे अधिक रेटिंग वाले NBFCs

D) All NBFCs without restrictions / सभी NBFCs

E) Only deposit-taking NBFCs / केवल जमा स्वीकार करने वाले NBFCs

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Reserve Bank of India issued new guidelines titled NBFC Branch Authorisation Directions, 2025.

• भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC ब्रांच ऑथराइजेशन दिशानिर्देश, 2025 जारी किए।

• NBFCs with net owned funds (NOF) above ₹50 crore and credit rating of AA or above can expand across India.

• ₹50 करोड़ से अधिक NOF और AA या उससे अधिक रेटिंग वाले NBFCs पूरे भारत में विस्तार कर सकते हैं।

• NBFCs with NOF up to ₹50 crore or lower ratings can open branches only within their home state.

• ₹50 करोड़ तक NOF या कम रेटिंग वाले NBFCs केवल अपने राज्य में शाखाएं खोल सकते हैं।

• NBFCs must notify RBI for branch expansion; if no objection is raised within 30 days, they can proceed.

• शाखा विस्तार के लिए NBFCs को RBI को सूचित करना होगा; 30 दिनों में आपत्ति न होने पर विस्तार किया जा सकता है।

• Applications must be submitted via the PRAVAAH portal.

• आवेदन PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे।

• National Housing Bank regulates Housing Finance Companies, which must inform NHB before opening branches and cannot open branches abroad.

• हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को शाखा खोलने से पहले NHB को सूचित करना होगा और वे विदेश में शाखाएं नहीं खोल सकतीं।

• NBFC-ICCs lending against gold must take prior RBI approval for opening more than 1,000 branches.

• सोने के बदले ऋण देने वाले NBFC-ICCs को 1000 से अधिक शाखाएं खोलने के लिए RBI की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

• For branch closure, NBFCs must give at least 3 months' public notice and inform RBI/NHB.

• शाखा बंद करने के लिए NBFCs को कम से कम 3 महीने पहले सार्वजनिक सूचना देनी होगी।

Ques: SEBI has approved which exchange's plan to set up a coal exchange in India?

प्रश्न: SEBI ने भारत में कोयला एक्सचेंज स्थापित करने की योजना को किस एक्सचेंज के लिए मंजूरी दी है?

A) National Stock Exchange (NSE) / नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

B) Bombay Stock Exchange (BSE) / बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

C) Multi Commodity Exchange of India (MCX) / मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया

D) India International Exchange (India INX) / इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज

E) National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX) / नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has approved the plan of Multi Commodity Exchange of India (MCX) to set up a coal exchange.

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) की कोयला एक्सचेंज स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है।

• MCX will create a new subsidiary named MCX Coal Exchange.

• MCX एक नई सहायक कंपनी "MCX Coal Exchange" स्थापित करेगा।

• Initially, MCX will hold 100% stake in this subsidiary.

• प्रारंभ में इस सहायक कंपनी में MCX की 100% हिस्सेदारी होगी।

• The investment for setting up the exchange will be up to ₹100 crore.

• इस एक्सचेंज की स्थापना के लिए ₹100 करोड़ तक का निवेश किया जाएगा।

• Approval will also be required from the Coal Controller Organisation of India.

• इसके लिए कोल कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया से भी अनुमति लेनी होगी।

• This initiative aims to bring transparency and efficiency in coal trading in India.

• इस पहल का उद्देश्य भारत में कोयला व्यापार में पारदर्शिता और दक्षता लाना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• MCX Established – 10 November 2003
• MCX की स्थापना – 10 नवंबर 2003
• Headquarters – Mumbai, Maharashtra
• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
• Regulator – SEBI (since 2015)
• नियामक – SEBI (2015 से)
• FMC merged with SEBI – 28 September 2015
• FMC का SEBI में विलय – 28 सितंबर 2015
• Key Indices:
– MCX iCOMDEX – Commodity index series
– BULLDEX – Bullion index (Gold & Silver)
– METLDEX – Base metals index
• Clearing Body – MCXCCL (Multi Commodity Exchange Clearing Corporation Limited)
• क्लियरिंग निकाय – MCXCCL (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

Ques : PayPoint India became the first private fintech to join which RBI system?

प्रश्न: PayPoint India किस RBI सिस्टम से जुड़ने वाली पहली प्राइवेट फिनटेक कंपनी बनी?

A. UPI / यूपीआई
B. NPCI Network / एनपीसीआई नेटवर्क
C. Centralised Payment System (CPS) / सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम (CPS)
D. IMPS / आईएमपीएस
E. Bharat BillPay / भारत बिलपे

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• PayPoint India Network became the first private fintech to get membership in RBI's Centralised Payment System (CPS).

• PayPoint India Network RBI के Centralised Payment System (CPS) की सदस्यता पाने वाली पहली प्राइवेट फिनटेक कंपनी बनी।

• It now gets direct access to RTGS and NEFT, reducing dependency on intermediary banks.

• अब इसे RTGS और NEFT तक सीधी पहुंच मिल गई है, जिससे मध्यस्थ बैंकों पर निर्भरता कम हो गई है।

• PayPoint has received its own IFSC code and can directly manage settlement with RBI.

• PayPoint को अपना IFSC कोड मिला है और अब यह सीधे RBI के साथ सेटलमेंट कर सकता है।

• CPS is operated by RBI as a unified platform for processing both large-value and retail transactions.

• CPS RBI द्वारा संचालित एक प्लेटफॉर्म है जो बड़े और रिटेल दोनों प्रकार के लेनदेन को प्रोसेस करता है।

Ques: As per SBI Research, what is India's projected GDP growth rate for FY27?

प्रश्न: SBI रिसर्च के अनुसार FY27 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है?

A) 5.5–6.0%
B) 6.0–6.5%
C) 6.8–7.1%
D) 7.5–8.0%
E) 8.0–8.5%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• SBI Research projects India's GDP growth at 6.8–7.1% in FY27.
• SBI रिसर्च ने FY27 में भारत की GDP वृद्धि 6.8–7.1% रहने का अनुमान लगाया है।
• India is facing global challenges such as oil price shocks and geopolitical tensions in West Asia.
• भारत तेल कीमतों के झटकों और पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है।
• Despite these challenges, strong domestic fundamentals are supporting economic growth.
• इन चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू आर्थिक आधार वृद्धि को समर्थन दे रहा है।
• This indicates resilience and stability in India's economy.
• यह भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिरता और मजबूती को दर्शाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• GDP – Gross Domestic Product
• GDP – सकल घरेलू उत्पाद
• FY27 – Financial Year 2026–27
• FY27 – वित्तीय वर्ष 2026–27
• SBI – State Bank of India
• SBI – भारतीय स्टेट बैंक
• SBI Chairman – Dinesh Kumar Khara
• SBI चेयरमैन – दिनेश कुमार खारा

Ques: CheQ has partnered with which bank to launch India's first LED-powered co-branded credit card?
प्रश्न: CheQ ने भारत का पहला LED-पावर्ड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है?

A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

C) SBI / भारतीय स्टेट बैंक

D) Axis Bank / एक्सिस बैंक

E) AU Small Finance Bank / एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• CheQ partnered with AU Small Finance Bank to launch India's first LED-powered co-branded credit card named "CheQ AU Credit Card".

• CheQ ने "CheQ AU Credit Card" नाम से भारत का पहला LED-पावर्ड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है।

• The card lights up during transactions using energy from the NFC field of POS terminals.

• यह कार्ड लेनदेन के दौरान POS टर्मिनल के NFC फील्ड से ऊर्जा लेकर प्रकाश करता है।

• It eliminates the need for a battery, making it more innovative and efficient.

• इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह अधिक नवीन और प्रभावी बनता है।

• The card supports dual networks – Visa for global transactions and RuPay for UPI payments.

• यह कार्ड दो नेटवर्क को सपोर्ट करता है – वैश्विक लेनदेन के लिए Visa और UPI भुगतान के लिए RuPay।

• This innovation enhances user experience and promotes digital payments in India.

• यह नवाचार उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाता है और भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• AU Small Finance Bank Established – 1996 (as NBFC), Bank status in 2017

• AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना – 1996 (NBFC के रूप में), 2017 में बैंक बना

• Headquarters – Jaipur, Rajasthan

• मुख्यालय – जयपुर, राजस्थान

• Visa – Global payment network
• Visa – वैश्विक भुगतान नेटवर्क
• RuPay – Indian domestic card payment network by NPCI
• RuPay – NPCI द्वारा संचालित भारतीय घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क

Ques: What is the theme of the RBI's 4th Global Hackathon "HaRBInger – Innovation for Transformation"?

प्रश्न: RBI के चौथे ग्लोबल हैकाथॉन "HaRBInger – Innovation for Transformation" का थीम क्या है?

A) Digital Payments for All / सभी के लिए डिजिटल भुगतान

B) Secure Banking: Powered by Identity, Integrity, and Inclusivity / सुरक्षित बैंकिंग: पहचान, ईमानदारी और समावेशन द्वारा संचालित

C) Future of FinTech Innovation / फिनटेक नवाचार का भविष्य

D) Inclusive Growth through Banking / बैंकिंग के माध्यम से समावेशी विकास

E) Smart Financial Ecosystem / स्मार्ट वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) launched the 4th edition of its Global Hackathon "HaRBInger – Innovation for Transformation".
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने ग्लोबल हैकाथॉन "HaRBInger – Innovation for Transformation" के चौथे संस्करण की शुरुआत की।
• The theme of the hackathon is "Secure Banking: Powered by Identity, Integrity, and Inclusivity".
• इस हैकाथॉन का थीम है "सुरक्षित बैंकिंग: पहचान, ईमानदारी और समावेशन द्वारा संचालित"।
• The hackathon focuses on three key problem statements.

• यह हैकाथॉन तीन प्रमुख समस्या कथनों पर केंद्रित है।
• These include Tokenised KYC, Offline CBDC, and Enhancing Trust.
• इनमें टोकनाइज़्ड KYC, ऑफलाइन CBDC और भरोसा बढ़ाना शामिल है।
• The initiative aims to promote innovation and strengthen the digital banking ecosystem.
• इस पहल का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और डिजिटल बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना है।

Ques: Who has been appointed as the part-time chairman of Bandhan Bank with approval from the Reserve Bank of India?
प्रश्न: Reserve Bank of India की मंजूरी से Bandhan Bank के पार्ट-टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
B) Debasish Panda / देबाशीष पांडा
C) Rajnish Kumar / रजनीश कुमार
D) Atanu Chakraborty / अतनु चक्रवर्ती
E) Amitabh Chaudhry / अमिताभ चौधरी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Bandhan Bank received RBI approval to appoint Debasish Panda as its part-time chairman.
• Bandhan Bank को Debasish Panda को पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त करने के लिए RBI की मंजूरी मिली।
• The appointment is for a tenure of 3 years, approved via an RBI letter dated April 22.
• यह नियुक्ति 3 वर्षों के लिए है, जिसे RBI ने 22 अप्रैल के पत्र के माध्यम से मंजूरी दी।
• In another development, Punjab National Bank partnered with fintech firm

Kiwi.

• एक अन्य विकास में Punjab National Bank ने फिनटेक कंपनी Kiwi के साथ साझेदारी की।

• The partnership aims to introduce credit-enabled UPI payments.

• इस साझेदारी का उद्देश्य क्रेडिट आधारित UPI भुगतान शुरू करना है।

• PNB will launch "PNB Kiwi Credit Card" on the RuPay network operated by National Payments Corporation of India.

• PNB, RuPay नेटवर्क (जो National Payments Corporation of India द्वारा संचालित है) पर "PNB Kiwi Credit Card" लॉन्च करेगा।

• This initiative will benefit around 180 million customers and allow UPI payments through credit cards.

• इस पहल से लगभग 180 मिलियन ग्राहकों को लाभ होगा और वे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान कर सकेंगे।

• It strengthens India's digital payment ecosystem and expands credit usage via UPI.

• यह भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करता है और UPI के माध्यम से क्रेडिट उपयोग को बढ़ाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Bandhan Bank – Private Sector Bank

• बंधन बैंक – निजी क्षेत्र का बैंक

• Founded – 2015

• स्थापना – 2015

• Headquarters – Kolkata

• मुख्यालय – कोलकाता

• Punjab National Bank – Public Sector Bank

• पंजाब नेशनल बैंक – सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक

• Founded – 1894

• स्थापना – 1894

• Headquarters – New Delhi

• मुख्यालय – नई दिल्ली

Ques: Vibha Padalkar, whose tenure was recently extended, is the MD & CEO of which company?

प्रश्न: हाल ही में जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया, विभा पाडलकर किस कंपनी की MD & CEO हैं?

A) ICICI Prudential Life Insurance / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस

B) SBI Life Insurance / एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस

C) Max Life Insurance / मैक्स लाइफ इंश्योरेंस

D) HDFC Life Insurance / एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस

E) LIC / एलआईसी

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Vibha Padalkar's tenure as MD & CEO of HDFC Life Insurance has been extended for five more years.

• विभा पाडलकर का HDFC लाइफ इंश्योरेंस के MD & CEO के रूप में कार्यकाल पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया है।

• She was first appointed to this position in 2018.

• उन्हें पहली बार 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था।

• HDFC Life Insurance is one of India's leading private life insurance companies.

• HDFC लाइफ इंश्योरेंस भारत की प्रमुख निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक है।

• The extension reflects the company's confidence in her leadership.

• यह विस्तार उनके नेतृत्व में कंपनी के विश्वास को दर्शाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• HDFC Life Insurance Founded – 2000

• HDFC लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना – 2000

• Headquarters – Mumbai, Maharashtra

• मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र

• Sector – Life Insurance
• क्षेत्र – जीवन बीमा
• Regulator – IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India)
• नियामक – IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण)

Ques: Which AI company's model 'Mythos' is being reviewed by the Reserve Bank of India and global regulators for potential cybersecurity risks to the banking sector?

प्रश्न: किस AI कंपनी के मॉडल 'Mythos' की बैंकिंग क्षेत्र में संभावित साइबर सुरक्षा जोखिमों के लिए Reserve Bank of India और वैश्विक नियामकों द्वारा समीक्षा की जा रही है?

A) OpenAI / ओपनAI

B) Google DeepMind / गूगल डीपमाइंड

C) Anthropic / एंथ्रोपिक

D) Meta AI / मेटा AI

E) Microsoft Copilot / माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• RBI is in talks with global regulators, Indian banks, and government officials to assess risks from Anthropic's AI model 'Mythos'.
• RBI वैश्विक नियामकों, भारतीय बैंकों और सरकारी अधिकारियों के साथ Anthropic के AI मॉडल 'Mythos' से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए चर्चा कर रहा है।
• Preliminary assessment suggests Mythos could increase cybersecurity risks by accelerating the discovery and exploitation of software vulnerabilities in financial systems.
• प्रारंभिक आकलन के अनुसार, Mythos सॉफ्टवेयर कमजोरियों की खोज और उनके दोहन को तेज कर सकता है, जिससे साइबर सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं।

• Regulators across Asia, Europe, and the US have already warned banks to strengthen cyber defences and preparedness in response to Mythos developments.

• एशिया, यूरोप और अमेरिका के नियामकों ने बैंकों को Mythos से जुड़े जोखिमों के मद्देनजर अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करने की चेतावनी दी है।

• Japan's financial regulator plans discussions with banks, while Australia's central bank is closely monitoring developments related to Mythos.

• जापान का वित्तीय नियामक बैंकों के साथ बैठक करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक Mythos से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है।

• RBI may directly engage with Anthropic to better understand the model's capabilities and associated risks to India's financial ecosystem.

• RBI, भारत के वित्तीय तंत्र पर संभावित प्रभावों को समझने के लिए Anthropic से सीधे संपर्क कर सकता है।

• Anthropic is a US-based AI safety company founded in 2021 by former OpenAI researchers including Dario Amodei and Daniela Amodei.

• Anthropic एक अमेरिका स्थित AI सुरक्षा कंपनी है, जिसकी स्थापना 2021 में OpenAI के पूर्व शोधकर्ताओं Dario Amodei और Daniela Amodei द्वारा की गई थी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Regulator – Reserve Bank of India (RBI)
• नियामक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
• RBI Governor – Sanjay Malhotra
• RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• AI Model – Mythos
• AI मॉडल – मिथोस
• Developed By – Anthropic (USA-based AI Company)
• विकसितकर्ता – Anthropic (अमेरिका स्थित AI कंपनी)

Ques: SEBI has reduced the minimum investment in Social Impact Funds to what amount to promote accessibility through the Social Stock Exchange

(SSE)?

प्रश्न: SEBI ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के माध्यम से निवेश को सुलभ बनाने के लिए सोशल इम्पैक्ट फंड्स में न्यूनतम निवेश राशि कितनी कर दी है?

A) ₹10,000
B) ₹5,000
C) ₹2,000
D) ₹1,000
E) ₹500

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has reduced the minimum investment in Social Impact Funds from ₹2 lakh to ₹1,000.

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोशल इम्पैक्ट फंड्स में न्यूनतम निवेश को ₹2 लाख से घटाकर ₹1,000 कर दिया है।

• This step aims to make social investing accessible to common investors.

• इस कदम का उद्देश्य आम निवेशकों के लिए सामाजिक निवेश को सुलभ बनाना है।

• The initiative is implemented through the Social Stock Exchange (SSE).

• यह पहल सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के माध्यम से लागू की जा रही है।

• SEBI has also enabled the use of Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) instruments on SSE.

• SEBI ने SSE पर ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल (ZCZP) उपकरणों के उपयोग को भी सक्षम किया है।

• ZCZP instruments help in transparent funding for social causes.

• ZCZP उपकरण सामाजिक उद्देश्यों के लिए पारदर्शी फंडिंग में मदद करते हैं।

• SSE is a platform where NGOs and social enterprises can raise funds from the public.

• SSE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां NGOs और सामाजिक उद्यम जनता से धन जुटा सकते हैं।

• It is a separate segment of stock exchanges like BSE and NSE and is regulated by SEBI.

• यह BSE और NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज का एक अलग सेगमेंट है और SEBI द्वारा विनियमित है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• SEBI Established – 1988 (Statutory status in 1992)
• SEBI की स्थापना – 1988 (1992 में वैधानिक दर्जा)
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई
• SSE Purpose – Fundraising for social causes
• SSE का उद्देश्य – सामाजिक उद्देश्यों के लिए धन जुटाना
• ZCZP Full Form – Zero Coupon Zero Principal
• ZCZP का पूरा नाम – ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल

Ques: As per the Draft PPI Master Directions 2026 issued by Reserve Bank of India, what is the minimum net worth required for a non-bank PPI issuer at the time of seeking authorisation, and how much must it be scaled up to within three years?

प्रश्न: Reserve Bank of India द्वारा जारी ड्राफ्ट PPI मास्टर दिशानिर्देश 2026 के अनुसार, अनुमति लेते समय गैर-बैंक PPI जारीकर्ता के लिए न्यूनतम नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए और इसे तीन वर्षों में कितना बढ़ाना होगा?

A) ₹2 crore → ₹10 crore (₹2 करोड़ → ₹10 करोड़)
B) ₹5 crore → ₹15 crore (₹5 करोड़ → ₹15 करोड़)
C) ₹10 crore → ₹25 crore (₹10 करोड़ → ₹25 करोड़)
D) ₹5 crore → ₹25 crore (₹5 करोड़ → ₹25 करोड़)
E) ₹15 crore → ₹25 crore (₹15 करोड़ → ₹25 करोड़)

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• RBI released draft Master Directions on PPIs proposing stricter capital requirements for non-bank issuers and tighter norms for low-KYC wallets.

• RBI ने PPIs पर ड्राफ्ट मास्टर दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें गैर-बैंक जारीकर्ताओं के लिए सख्त पूंजी आवश्यकताएं और कम-KYC वॉलेट के लिए कड़े नियम प्रस्तावित हैं।

• Non-bank PPI issuers must have a minimum net worth of ₹5 crore at authorisation, to be increased to ₹15 crore by the end of the third financial year and maintained thereafter.

• गैर-बैंक PPI जारीकर्ताओं को अनुमति के समय ₹5 करोड़ की नेट वर्थ रखनी होगी, जिसे तीसरे वित्त वर्ष तक ₹15 करोड़ तक बढ़ाना होगा और आगे भी बनाए रखना होगा।

• Small PPIs (Minimum KYC): Only one wallet per customer, validity up to 2 years, no reissue after expiry, usable only for goods and services (no cash withdrawal or P2P transfer), and cash loading capped at ₹10,000 per month.

• स्मॉल PPI (न्यूनतम KYC): प्रति ग्राहक केवल एक वॉलेट, अधिकतम 2 वर्ष की वैधता, समाप्ति के बाद पुनः जारी नहीं, केवल वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपयोग (कोई नकद निकासी या P2P ट्रांसफर नहीं), और ₹10,000/माह तक कैश लोडिंग।

• Full-KYC PPIs: Balance limit of ₹2 lakh retained, P2P transfers capped at ₹25,000 per month, minimum validity of 1 year, and only one full-KYC PPI per holder.

• फुल-KYC PPI: ₹2 लाख की बैलेंस सीमा बरकरार, P2P ट्रांसफर ₹25,000/माह तक सीमित, न्यूनतम 1 वर्ष की वैधता, और प्रति धारक केवल एक फुल-KYC PPI।

• Issuers must keep PPI funds in a separate escrow account with a Scheduled Commercial Bank, used only for authorised PPI business.

• जारीकर्ताओं को PPI राशि को एक अलग एस्क्रो खाते में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास रखना होगा, जिसका उपयोग केवल अधिकृत PPI कार्यों के लिए होगा।

• On inactivity or closure, remaining balance must be transferred back to the source or a verified bank account.

• निष्क्रियता या बंद होने पर, शेष राशि को स्रोत खाते या सत्यापित बैंक खाते में वापस भेजना होगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Directions – Draft Master Directions on PPIs, 2026

- दिशानिर्देश – ड्राफ्ट PPI मास्टर दिशानिर्देश, 2026
- Issued By – Reserve Bank of India (RBI)
- जारीकर्ता – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- RBI Governor – Sanjay Malhotra
- RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Announced – April 22, 2026
- घोषणा – 22 अप्रैल 2026
- PPI Full Form – Prepaid Payment Instrument
- PPI का पूरा नाम – प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट
- Net Worth (At Authorisation) – ₹5 crore
- नेट वर्थ (अनुमति के समय) – ₹5 करोड़
- Net Worth (Within 3 Years) – ₹15 crore
- नेट वर्थ (3 वर्षों में) – ₹15 करोड़
- Small PPI – Max validity 2 years, only for goods/services, one per customer
- स्मॉल PPI – अधिकतम 2 वर्ष वैधता, केवल वस्तु/सेवा हेतु, प्रति ग्राहक एक
- Small PPI Cash Loading – ₹10,000/month
- स्मॉल PPI कैश लोडिंग – ₹10,000/माह
- Small PPI Balance Cap – ₹10,000
- स्मॉल PPI बैलेंस सीमा – ₹10,000
- Full-KYC PPI Balance – ₹2 lakh
- फुल-KYC PPI बैलेंस – ₹2 लाख
- Full-KYC P2P Transfer Cap – ₹25,000/month
- फुल-KYC PPI P2P ट्रांसफर सीमा – ₹25,000/माह

Ques: The tenure of MD & CEO of which banks has been extended by 3 years recently?

प्रश्न: हाल ही में किन बैंकों के MD & CEO का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है?

A) SBI & PNB / एसबीआई और पीएनबी

B) BoB & BoI / बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया

C) Canara Bank & UCO Bank / केनरा बैंक और यूको बैंक

D) ICICI & HDFC / आईसीआईसीआई और एचडीएफसी

E) Axis & IDBI / एक्सिस और आईडीबीआई

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Central Government has extended the tenure of MD & CEOs of Bank of Baroda and Bank of India by 3 years.

• केंद्र सरकार ने Bank of Baroda और Bank of India के MD & CEO का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ाया है।

• Debadatta Chand (BoB) and Rajneesh Karnatak (BoI) will continue in their respective roles.

• Debadatta Chand (BoB) और Rajneesh Karnatak (BoI) अपने पदों पर बने रहेंगे।

• The extension for Rajneesh Karnatak is effective from April 29, 2026.

• रजनीश कर्नाटक का कार्यकाल विस्तार 29 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।

• The extension for Debadatta Chand is effective from July 1, 2026.

• देबदत्ता चंद का कार्यकाल विस्तार 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा।

• The decision aims to ensure leadership continuity and stability in public sector banks.

• यह निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नेतृत्व की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Bank of Baroda HQ – Vadodara

• बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्यालय – वडोदरा

• Bank of India HQ – Mumbai

• बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय – मुंबई

• Tenure Extension – 3 years

• कार्यकाल विस्तार – 3 वर्ष

• BoB MD & CEO – Debadatta Chand
• BoB MD & CEO – देबदत्ता चंद
• BoI MD & CEO – Rajneesh Karnatak
• BoI MD & CEO – रजनीश कर्नाटक

Ques: As per RBI's "Digital Payments – E-mandate Framework, 2026", recurring transactions above what amount require additional authentication?

प्रश्न: RBI के "डिजिटल पेमेंट्स – ई-मैन्डेट फ्रेमवर्क, 2026" के अनुसार कितनी राशि से अधिक के आवर्ती लेनदेन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण आवश्यक है?

A) ₹15,000
B) ₹10,000
C) ₹5,000
D) ₹50,000
E) ₹1,00,000

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India issued consolidated guidelines titled "Digital Payments – E-mandate Framework, 2026".
• भारतीय रिजर्व बैंक ने "डिजिटल पेमेंट्स – ई-मैन्डेट फ्रेमवर्क, 2026" नामक समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
• These norms apply to all payment system providers handling recurring payments through cards, prepaid payment instruments, and UPI.
• ये नियम कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और UPI के माध्यम से आवर्ती भुगतान संभालने वाले सभी प्रदाताओं पर लागू होते हैं।
• Customers must complete a one-time registration process with Additional Factor of Authentication (AFA).
• ग्राहकों को अतिरिक्त प्रमाणीकरण (AFA) के साथ एक बार का पंजीकरण करना होगा।
• Recurring transactions exceeding ₹15,000 require additional authentication.

• ₹15,000 से अधिक के आवर्ती लेनदेन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण आवश्यक है।
• However, transactions up to ₹1 lakh are allowed without additional authentication in specific categories like insurance premiums, mutual funds, and credit card bill payments.
• हालांकि, बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड बिल जैसे कुछ मामलों में ₹1 लाख तक के लेनदेन बिना अतिरिक्त प्रमाणीकरण के किए जा सकते हैं।
• Issuers must specify validity period and allow users to modify or withdraw mandates anytime.
• जारीकर्ता को वैधता अवधि स्पष्ट करनी होगी और उपयोगकर्ताओं को किसी भी समय मैन्डेट बदलने या वापस लेने की सुविधा देनी होगी।
• Advance alerts are mandatory at least 24 hours before debit, except for FASTag and NCMC auto-replenishment.
• डेबिट से कम से कम 24 घंटे पहले अग्रिम सूचना देना अनिवार्य है, हालांकि FASTag और NCMC ऑटो-रीचार्ज पर यह लागू नहीं है।
• No charges can be levied for availing e-mandate services.
• ई-मैन्डेट सेवा के लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Ques: Who has been appointed as Executive Director (ED) of AU Small Finance Bank?

प्रश्न: AU Small Finance Bank के कार्यकारी निदेशक (ED) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा

B) Vivek Tripathi / विवेक त्रिपाठी

C) Amitabh Chaudhry / अमिताभ चौधरी

D) Shyam Srinivasan / श्याम श्रीनिवासन

E) Rajnish Kumar / रजनीश कुमार

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Reserve Bank of India approved the appointment of Vivek Tripathi as Executive Director (ED) of AU Small Finance Bank.

• Reserve Bank of India ने Vivek Tripathi को AU Small Finance Bank के कार्यकारी निदेशक (ED) के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी।

• The appointment is for a period of three years.

• यह नियुक्ति तीन वर्षों के लिए की गई है।

• He will also serve as a Whole-time Director (WTD) of the bank.

• वह बैंक में पूर्णकालिक निदेशक (WTD) के रूप में भी कार्य करेंगे।

• He is currently serving as Chief Credit Officer (CCO) and has been associated with the bank since 2014.

• वह वर्तमान में मुख्य क्रेडिट अधिकारी (CCO) हैं और 2014 से बैंक से जुड़े हुए हैं।

• The appointment will be effective from April 24, 2026, subject to shareholder approval.

• यह नियुक्ति 24 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी, जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• RBI Established – 1935

• आरबीआई की स्थापना – 1935

• Headquarters – Mumbai

• मुख्यालय – मुंबई

• Governor – Sanjay Malhotra

• गवर्नर – Sanjay Malhotra

• AU Small Finance Bank HQ – Jaipur

• एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मुख्यालय – जयपुर

Ques: Export-Import Bank of India has extended a $100 million loan to which organization?

प्रश्न: एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने $100 मिलियन का ऋण किस संगठन को प्रदान किया है?

A) African Development Bank / अफ्रीकी विकास बैंक

B) World Bank / विश्व बैंक

C) Africa Finance Corporation / अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन

D) International Monetary Fund / अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

E) Asian Infrastructure Investment Bank / एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Export-Import Bank of India has extended a $100 million (approx ₹830 crore) loan to Africa Finance Corporation (AFC).

• एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन (AFC) को $100 मिलियन (लगभग ₹830 करोड़) का ऋण प्रदान किया है।

• The loan will support AFC's mandate to accelerate development of critical infrastructure and industrial assets across Africa.

• यह ऋण अफ्रीका में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और औद्योगिक संपत्तियों के विकास को तेज करने में AFC की सहायता करेगा।

• Africa Finance Corporation (AFC) is a leading infrastructure solutions provider in Africa.

• अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन (AFC) अफ्रीका में एक प्रमुख अवसंरचना समाधान प्रदाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

• Africa Finance Corporation Founded – 2007
• अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना – 2007
• Headquarters – Lagos, Nigeria
• मुख्यालय – लागोस, नाइजीरिया
• EXIM Bank of India Established – 1982
• भारत के EXIM बैंक की स्थापना – 1982
• Headquarters – Mumbai
• मुख्यालय – मुंबई